

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 5 नवम्बर, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में राजभवन परिसर में निर्माणाधीन आडिटोरियम एवं सचिवालय भवन के विद्युत आपूर्ति के लिये सर्विस कनेक्शन कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपयुक्त विषयक सचिव श्री राज्यपाल के पत्र सं0-1833/जो0एस0/C-104/2008 दिनांक 18-09-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन परिसर में निर्माणाधीन आडिटोरियम एवं सचिवालय भवन के विद्युत आपूर्ति के लिये सर्विस कनेक्शन कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रुपये 23.42 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 23.42 लाख (रुपये तेईस लाख बयालीस हजार मात्र) की ही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. कार्य करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
6. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
7. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय और उपयोग के बाद इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि समय से भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा सकें। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 का भी अनुपालन किया जाय।
8. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य- आयोजनागत-800-अन्य भवन-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये-0101-12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-815/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)

अनु सचिव

संख्या:- 3192 (1)/III (2)/08-15(प्रा0आ0)/2007 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरोय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 3- निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फाइनेन्स कमीशन डिविजन, 11 ब्लाक 5वाँ तल, सी. जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
- 6- अपर सचिव वित्त (बजट) अनुभाग उत्तराखण्ड।
- 7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी।
- 10- अधीक्षण अभियन्ता नवां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
- 11- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
- 13- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Mihima

(महिमा)

अनु सचिव